www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 267 | जौनपुर सोमवार, 18 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद उच्चस्तरीय जांच के आदेश

कोटा, एजेंसी। मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को तिरुवनंतपुरमदृहजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद इसकी उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जिस कोच में आग लगी, उससे समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है। आग लगने के बाद रेलवे ने देशभर में कोचों और रेलवे से जुड़े फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच शुरू कर दी है, ताकि सुरक्षा तैयारियों का आकलन किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बयान में कहा, सुबह करीब 5:15 बजे त्रिवेंद्रम–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12431) की पीछे की दो बोगियों में आग लग गई। यह घटना कोटा मंडल के नागदा क्षेत्र में लूनी रिछा और विक्रमगढ़ आलो स्टेशनों के बीच हुई। प्रभावित कोचों में एक गार्ड कोच और एक एसी 3 टियर कोच शामिल था। रेलवे के अनुसार, आग लगने की जानकारी मिलते ही ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई तुरंत बंद कर दी गई, ताकि कोई बड़ा खतरा न हो। इसके बाद प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। श्रीवास्तव ने कहा कि आग से प्रभावित बी–1 कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। रेलवे कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के काम में जुट गए।

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल उस रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई टल गई, जिसमें बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसी दौरान शिकायतकर्ता के वकील विकास त्रिपाठी ने चुनाव आयोग से प्राप्त कुछ दस्तावेजों को कोर्ट रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि फिलहाल उनकी मांग ट्रायल शुरू कराने की नहीं है बल्कि पुलिस जांच करवाने की है। उनका कहना था कि मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी।

पीएम नरेन्द्र मोदी स्वीडन पहुंचे, पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्राओं के बाद रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। यह उनकी पांच देशों की यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के आगमन को विशेष महत्व देते हुए स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने उनके विमान को स्वीडिश एयरस्पेस में एस्कॉर्ट किया। यह भारत और स्वीडन के बीच बढ़ते रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड में कई उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल हुए। इन दौरों के बाद वे सीधे स्वीडन पहुंचे, जहां उनकी दो दिवसीय (17–188 मई) आधिकारिक यात्रा प्रस्तावित है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और स्वीडन के बीच सहयोग को नई दिशा देना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, ग्रीन ट्रांजिशन, स्टार्टअप, और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। भारत ने वर्ष 2018 में पहली भारत–नॉर्डिक शिखर बैठक के दौरान स्वीडन की यात्रा की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को और गहरा करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच होने वाली वार्ता में भारतदृस्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इसमें रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषय शामिल होंगे।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, महिला स्टार्टअप्स को मिलेगा 10 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपए तक के कोलैटरल–फ्री लोन (बिना गिरवी ऋण) की व्यवस्था की है, जिसकी गारंटी स्वयं दिल्ली सरकार लेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार शाम उत्तर पश्चिम दिल्ली स्थित यूनिटी वन मॉल, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास आयोजित दो दिवसीय 'मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) मेला–2026' के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 'स्वदेशी अपनाओ', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' का विजन देश के सामने रख रहे हैं। यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को बाजार से जोड़ने का सशक्त प्रयास है। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार अब मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में स्वदेशी उत्पादों के लिए नियमित रूप से उचित मंच उपलब्ध कराएगी, ताकि स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं घरों में रहकर छोटे–छोटे उद्योगों और हस्तनिर्मित उत्पादों के माध्यम से न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने हस्तशिल्प, खादी, घरेलू उत्पाद और हस्तनिर्मित वस्तुएं गुणवत्ता में किसी से कम नहीं हैं, जरूरत केवल बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की है।

शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, सात राष्ट्रीय राजमार्ग को NHAI-NHIDCL को सौंपने की दी मंजूरी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बदलावों का दौर जारी है। अब नई शुभेंदु सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग के नेशनल हाईवे के सात हिस्सों को NHAIऔर NHIDCL को सौंपने के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से राज्य के महत्वपूर्ण सड़क गलियारों पर लंबे समय से रुके हुए निर्माण कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। ये सड़कें अब तक राज्य के लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा के पास थीं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन सड़कों को सौंपने के लिए कई बार अनुरोध किया था। इसके बावजूद यह प्रस्ताव लगभग एक साल से अटका हुआ था। मुख्य सचिव के कार्यालय ने शनिवार को एक प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी।

विकास कार्यों में आएगी तेजी

प्रेस नोट में बताया गया कि औपचारिक रूप से सड़कें न सौंपे जाने के कारण इन पर विकास कार्य रुके हुए थे। अब मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसियां बिना किसी देरी के काम शुरू कर सकेंगी। छभ।प् को सौंपी गई सड़कों में NH–312 का 329.6 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है। यह सड़क जंगीपुर, ओमरपुर, कृष्णानगर, बनगांव और बशीरहाट को भारत–बांग्लादेश सीमा पर स्थित घोजाडांगा से जोड़ती है। इसके अलावा बिहार–पश्चिम बंगाल सीमा से गजोल तक NH–31 और फरक्का तक NH–33 को भी NHAI को दिया गया है। अन्य गलियारों में हाशिमारा–जयगांव मार्ग (भारत–भूटान सीमा तक), बरदिघी–मैनागुड़ी–चंगराबंदा मार्ग (बांग्लादेश सीमा तक) और सिलीगुड़ी–कुर्सियांग–दार्जिलिंग पहाड़ी सड़क शामिल हैं।

अमित शाह ने अहमदाबाद में 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' और 'GREMI सिटी कैंपस' का किया उद्घाटन

अहमदाबाद, एजेंसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद, गुजरात में नवनिर्मित 'मिलियन माइंड्स टेक पार्क' और 'GREMI सिटी कैंपस' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

मोदी सरकार के विजन को बड़ा मील का पत्थर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना देश को तकनीक और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आगे ले जाना है, जिसे यह परियोजना एक बड़े मील के पत्थर के रूप में आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी,

इनोवेशन, उच्च कौशल और उद्यमिता आधारित उद्योगों का विस्तार गुजरात को न्यू–एज टेक्नोलॉजी का नेतृत्वकर्ता बनाएगा। अमित शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि 2002 से गुजरात में औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को व्यवस्थित रूप दिया गया है। उनके अनुसार, गुजरात ने हर क्षेत्र में मजबूत कदम बढ़ाए हैं और औद्योगिक विकास में देश के शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बनाई है। अमित शाह ने कहा कि अब गुजरात को सेवा क्षेत्र में भी शीर्ष तीन राज्यों में लाने का लक्ष्य है। इसके लिए अहमदाबाद को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों के समकक्ष विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह टेक पार्क 13.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026' जारी किया है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं होंगे। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करना और लोगों को तेजी से न्याय दिलाना है। माना जा रहा है

कि जजों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबे समय से लंबित केसों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956' में संशोधन करते हुए जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश केंद्र सरकार के उस फैसले के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों के पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' को संसद में पेश करने का फैसला लिया गया था।

सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते कामकाज और लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था। नए जजों की नियुक्ति से अदालत की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सुनवाई में हो रही देरी को कम करने में मदद मिलेगी।

पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर सीएम मान का तंज

पंजाब, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए नागरिकों से विदेश यात्राएं और सोने की खरीद कम करने का आग्रह करने के बावजूद वे विदेश यात्राएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मितव्ययिता की अपील के कुछ ही दिनों बाद नीदरलैंड यात्रा को लेकर उन पर निशाना साधते हुए मान ने पत्रकारों से कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री को अपनी विदेश यात्राएं बंद करनी चाहिए। अब वे कहां हैं? वे नीदरलैंड गए हैं। वे 3–4 और देशों का दौरा करेंगे। उन्होंने लोगों से यात्रा से बचने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वे विदेश यात्रा पर चले गए। आप सब कुछ बंद कर रहे हैं... सोना न खरीदें, विदेश यात्राएं न करें, घर से काम करें। प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के छह दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के फोन कॉल पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मान ने पूछा कि प्रधानमंत्री घर से काम क्यों नहीं करते? पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि हम 'विश्वगुरु' बनने वाले थे, लेकिन हम 'विश्वचेले' बन गए हैं। युद्ध कहीं और चल रहा है, लेकिन पाबंदियां यहां लगाई जा रही हैं। किसी और देश ने ऐसा (पाबंदियां) क्यों नहीं लागू कीं? वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ईंधन खुदरा विक्रेताओं को हो रहे भारी नुकसान के बीच, शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो चार साल से अधिक समय में पहली बार हुई है।

तमिलनाडु की सत्ता संभालने के बाद सीएम विजय का पहला दिल्ली दौरा

तमिलनाडु, एजेंसी। मुख्यमंत्री विजय नई दिल्ली की यात्रा पर जा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद, देश के बड़े नेताओं के साथ उनकी यह पहली बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वे कई उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विजय इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में तमिलनाडु के विकास से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें मुख्य रूप से राज्य के लिए मिलने वाला बजट, सड़कों और इमारतों से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और नई सरकार के तहत राज्य के कामकाज के तरीके शामिल हैं।

इन बड़े नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात तय करने के लिए बातचीत चल रही है। सरकारी नियमों के तहत, विजय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इन मुलाकातों से आने वाले समय में तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच के रिश्तों की दिशा तय होगी।

बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी, वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द होगी शुरू - रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु–मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क और मजबूत होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में रेलवे राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

बेंगलुरु–मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द

रेल मंत्री ने घोषणा की कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सेवा यात्रियों के लिए तेज, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा का नया विकल्प बनेगी।

कर्नाटक–महाराष्ट्र संपर्क को मिलेगी नई मजबूती

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह नई एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में रेलवे क्षेत्र में निवेश और परियोजनाओं की गति बढ़ी है, जिससे राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़े स्तर पर पुनर्विकास

रेल मंत्रालय के अनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक में 2,160 करोड़ रुपए की लागत से 61 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से 9 स्टेशन पहले ही तैयार हो चुके हैं। बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन का पुनर्विकास 485 करोड़ रुपए और यशवंतपुर स्टेशन का

पुनर्विकास 367 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा है।

कर्नाटक में रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार

रेल मंत्री ने बताया कि 2014 के बाद से कर्नाटक में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। इसके साथ ही कई खंडों में विद्युतीकरण कार्य भी पूरा किया गया है, जिससे राज्य का रेल नेटवर्क आधुनिक और अधिक सक्षम बना है।

बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना पर तेजी से काम

बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के चारों कॉरिडोर पर काम जारी है। बैयप्पनहल्ली–चिक्कबनवारा और हीलालिगेदृराजनुकुंटे कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और स्टेशन निर्माण चल रहा है। यह परियोजना बेंगलुरु के प्रमुख क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मराठाहल्ली और हेब्बल को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।

संपादकीय

भारत की संभावनाओं पर लगते ग्रहण का परिणाम

सात साल बाद बर्नस्टीन रिसर्च ने प्रधानमंत्री को अपनी दूसरी चिठ्ठी लिखी है, जिसमें वह भारत को लेकर चिंता में डूबा नजर आया है। इसमें उसने भारत की विकास कथा के लिए खड़ी कठिन चुनौतियों पर रोशनी डाली है। अंतरराष्ट्रीय इक्विटी रिसर्च एवं ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने पत्र लिख कर प्रधानमंत्री को उन गंभीर आर्थिक स्थितियों से आगाह किया है, जो भारत की विकास कथा के लिए खतरा बन रही हैं। इसी फर्म ने 2019 के आम चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद भी नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। तब बर्नस्टीन भारत की संभावनाओं को लेकर आशावादी थी। तब उसने कहा था कि पूंजी मुहैया करवा कर बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाए और दिवालिया संहिता (आईबीसी कोड) को कारगर बना दिया जाए, तो आर्थिक विकास की पटरी पर भारत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। अब सात साल बाद बर्नस्टीन रिसर्च भारत को लेकर गहरी चिंता में डूबा नजर आया है। उसने भारत की विकास कथा के लिए खड़ी चुनौतियों पर रोशनी डाली है। कहा है कि रोजगार का प्रश्न अब चक्रीय नहीं रहा, बल्कि यह भारत के अस्तित्व से जुड़ गया है। बर्नस्टीन ने कहा है कि भारतीय कृषि 1970 के दशक के नीति–जाल में अटकी हुई है। नतीजतन, जीडीपी में 15–16 प्रतिशत योगदान के बावजूद इस पर श्रम शक्ति का 42–45 प्रतिशत हिस्सा निर्भर है। पत्र में आगाह किया गया है कि भारत के सामने यह स्थायी खतरा खड़ा है, जिससे वह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का निर्माता नहीं, बल्कि उपभोक्ता भर बन कर रह जाएगा। उधार मैनुफैक्चरिंग में गहराई के अभाव में देश की महत्त्वाकांक्षाएं ठोस आधार नहीं पा सकी हैं। जिन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है, उनमें भी चीनी पाट–पुर्जों पर 30–40 प्रतिशत निर्भरता बनी हुई है। बर्नस्टीन ने चेताया है कि नकदी ट्रांसफर की योजनाओं की आई बाढ़ के कारण भारत के निम्न उत्पादकता वाला देश बने रह जाने की स्थिति बन रही है। और आखिर में बर्नस्टीन ने दो–टूक कहा है कि कोई देश अनुसंधान एवं विकास पर अपनी जीडीपी का महज 0.6– 0.7 प्रतिशत खर्च कर विकसित नहीं हो सकता। ये वो बातें हैं, जिनकी ओर देश के लिए चिंतित वर्ग अक्सर ध्यान खींचता है। मगर अब खास बात यह है कि वित्तीय पूंजीवाद की प्रमुख वैश्विक संस्थाएं भी वही बात कहने लगी हैं। यह भारत की संभावनाओं पर लगते ग्रहण का परिणाम है।

भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन

डॉ. सुधीर सक्सेना

शुरूआत सचमुच शानदार थी। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश थाय दमन, शोषण और दीनता का शिकार दास राष्ट्र। महात्मा गांधी विश्व–इतिहास के अलीक–योद्धा के तौर पर परिदृश्य में उभर रहे थे। सारा राष्ट्र आजादी के लिये व्यग्र था। ऐसे में एक नये वैचारिक–आंदोलन ने भारत में प्रवेश किया और सर्वथा अलहदा मिजाज की एक पार्टी ने भारत में जन्म लिया। इसमें केन्द्रीय और अग्रणी भूमिका थी एमएन राय यानि मानवेंद्र नाथ राय की, जिन्हें सोवियत संघ जैसे विशाल राष्ट्र के सर्वेसर्वा बलादिमीर इलिच लेनिन का संग–साथ और विश्वास हासिल था। हुआ यह कि 17 अक्टूबर, सन 1920 को पामीर पार ताशकंद में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस की बैठक हुई और इसने भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की पूर्वपीठिका रच दी। विचार मंथन और सांगठनिक प्रयासों के बाद अंततरू 25 दिसंबर, सन 1925 को भारत के मैनचेस्टर कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसके शुरूआती नेताओं में एमएन राय के अलावा अबनि मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफीक सिद्दिकी प्रमुख थे। 25 दिसंबर, सन 2025 से काल गणना करें तो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की एक सदी पूरी हो चुकी है। इस मान से यदि एक शती के वृत्तांत यानि कम्युनिस्ट आंदोलन के हश्र को बांचें तो बहुत दिलचस्प चटख और धूमिल रंगों का कोलाज उभरता है। बालीवुड की फिल्म की तर्ज पर हम इसे राइज एण्ड फाल आफ कम्युनिस्ट मूवमेंट–कम्युनिस्ट आंदोलन का उत्थान और पतन भी कह सकते हैं। इस वृत्तांत में लंबे रक्तिम संघर्ष हैं और गर्वीली सफलतायें भी। वहां विफलतायें हैं और बिखराव भी। वहां विमर्श है और विभ्रम भी। संघर्ष, निष्ठा, समर्पण, बलिदान और अनेक महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद इसकी अंततरू शोकांतिका में परिणिति विस्मयकारी है, जो बहुतों को शोकाकुल करती है, तो बहुतों को हर्षित भी। क्या वजह है कि ऐसा हुआ? क्या ऐसा होना वृहत्तर समाज के स्वास्थ्य और भविष्य के लिहाज से सुखद है अथवा इसे विडंबना या त्रासदी माना जाये। विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन और भारत के रिश्तों से शुरू करें तो कई अहम निष्कर्ष निकलते हैं। आंदोलन के प्रणेता कार्ल मार्क्स पहले मनीषी हैं, जिसने सन 1857 के अंग्रेजों द्वारा प्रचारित गदर को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। मार्क्स की भारत के इतिहास में गहरी रूचि थी और वह भारत की आजादी के हिमायती थे। इसमें कोई शक नहीं कि बीसवीं सदी विश्व स्तर पर वाम विचारों की सदी थी और इसने सभी महाद्वीपों में करोड़ों लोगों को वैचारिक तौर पर प्रभावित और आंदोलित किया। श्रमिकों, लेखकों और कलाकारों पर इसका प्रभाव अभूतपूर्व था। श्रम की महत्ता और गरिमा का पाठ प्रस्तुत कर इसने अनेक देशों में कू–दे–ता (तख्तापलट) की स्थितियां पैदा कींय साहित्य कला और संस्कृति में नये आंदोलन उपजाये, पूंजीवादी–ईमान को डगमग किया, श्रमिकों के लिए बेहतर वातावरण सृजित किया, पारंपरिक रूढ़ियों के प्रति असंतोष उपजाया, उपनिवेशवाद के खिलाफ अलख जगाई और युवा वर्ग की आंखों में नये सपने आंजे। उसने गैर–बराबरी के खिलाफ बराबरी, शोषण के खिलाफ मुक्ति और दासता के खिलाफ स्वतंत्रता की हिमायत की। यह विश्व इतिहास में परंपरा और रूढ़ियों के खिलाफ विचलन और हस्तक्षेप का सर्वथा भिन्न और अपूर्व उपक्रम था। हम स्तालिन, गोर्की, चेखव, माओ, होची मिन्ह, चेग्वेरा, कास्त्रो, नाजिम, हिकमत, फैज, रेजिस द ब्रे, चार्ली चौप्लिन आदि की बात न कर यदि भारतीय परिदृश्य पर भी दृष्टिपात करें तो बड़े और सितारा नेताओं, कवियों, कलाकारों, दार्शनिकों और कार्यकर्ताओं में कौन है, जिसे सोवियत क्रांति अथवा साम्यवादी विचारों व आंदोलनों ने प्रभावित नहीं किया? पं. नेहरू से लेकर भगत सिंह तक, रबींद्रनाथ ठाकुर से लेकर प्रेमचंद तक, राजकपूर से लेकर बलराज साहनी तक, माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी तक नामों की एक अछोर कतार है, जिन्हें साम्यवादी विचारों ने आलोड़ित किया। शहीदे आजम भगत सिंह तो फांसी के तख्ते की ओर जाने से कुछ क्षण पहले तक लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे.... और लेनिन? लेनिन तब नहीं थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि लेनिन क्या थे? लेनिन भारत से गेहरे प्रेम में डूबी हुई – महान क्रांतिकारी शख्सियत थे। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा, जालियांवाला कांड की निंदा की, तिलक को मांडले जेल भेजन का विरोधा किया, महात्मा गांधी की अगुवाई में आजादी की लड़ाई का समर्थन किया, भारत में अकाल पर अंग्रेज–नीतियों की निंदा की और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी समेत सैकड़ों युवकों के विचारों को प्रज्वलित किया। निश्चित ही, लेनिन अपने प्रति भारतवासियों के बेहतर सोच और सलूक के हकदार हैं। बाद के दौर को देखें तो भी सोवियत और फिर रूस के शासक और जन भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और सदिच्छा रखते हैं।

सत्ता संभालते ही हिंदुत्व मॉडल के जरिये बंगाल में बड़े बदलाव ले आये सुवेंदु अधिकारी

नीरज

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही चुनावी वादों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाने तो शुरू कर ही दिये हैं साथ ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में तेज बदलावों का दौर भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें राज्य की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उनके गढ़ में पराजित कर सत्ता तक पहुंचे सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के केवल 48 घंटे के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन बड़े निर्णयों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया कि नई सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक बदलाव चाहती है। नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी। कोलकाता के रेड रोड क्षेत्र में सार्वजनिक नमाज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार ने पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुवेंदु अधिकारी सरकार ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2023 के पंचायत चुनावों के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। इन मामलों को पिछली सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित और बंद मामलों की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों को भी दोबारा जांच के दायरे में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में मारे गए तीन सौ इक्कीस भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार यदि चाहें तो सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। यह फैसला राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर भाजपा के लंबे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा, नई सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई करने और पुलिस को बिना राजनीतिक दबाव के काम करने की खुली छूट देने की घोषणा की है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और किसी की राजनीतिक पहचान को महत्व न दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि कानून व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाएगा। साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के मुद्दे पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य में अवैध पशु बाजारों को बंद करने और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर चौबीस परगना जिलों में चल रहे अवैध पशु बाजारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को पैंतालीस दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अवैध घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन में हो रहे बदलावों पर रोक लगेगी। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर भी सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब किसी भी पशु के वध से पहले उसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र नगर निकाय प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त सहमति से जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही इसकी अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर छह महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। नई सरकार के इस कदम को कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही राज्य में लंबे समय से चर्चा में रहे सिंडिकेट राज और अवैध खनन पर भी सरकार ने कार्रवाई का संकेत दिया है। जिला और प्रखंड स्तर पर सक्रिय कथित सिंडिकेट नेटवर्क को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पिछली व्यवस्था में निर्माण सामग्री और कई क्षेत्रों में प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण था, जिसे खत्म करना आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में विभिन्न बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों और गैर वैधानिक संस्थाओं में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। साठ वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। नई सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते तेजी से पूरा करने को कहा है। साथ ही राज्य की नई भाजपा सरकार ने शिक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मोर्चे पर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार कक्षाएं शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को वंदे मातरम् के छहों पद गाने होंगे। सरकार का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम् को जन गण मन के समान दर्जा दिए जाने के बाद इस निर्णय को और अधिक महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके अलावा, कानूनी ढांचे में बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता को राज्य में लागू करने की घोषणा भी की गई है। यह नया आपराधिक कानून पुराने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कार्यान्वयन लंबित था। नई सरकार ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।

सोना न खरीदने की अपील : तब और अब का भारत

गिरीश

विदेश समाचार यह भी साफ रहना चाहिए कि सोने पर संयम से हासिल क्या होता है। अगर सोने का आयात घटता है तो विदेशी मुद्रा पर दबाव कुछ कम पड़ता है, चालू खाता घाटा नियंत्रित होता है और रुपये को थोड़ी राहत मिलती है। यह सब वास्तविक आर्थिक लाभ हैं। लेकिन इससे रोजगार पैदा नहीं होता, किसी की आय नहीं बढ़ती और न ही गरीबी सीधे कम होती है। इसलिए सोने पर संयम को उसी रूप में समझना चाहिए जिस रूप में वह है? हाल ही में हैदराबाद से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि जहां तक हो सके सोना मत खरीदिए, विदेश यात्राएं टालिए, तेल बचाइए और जितना संभव हो उतना घर से काम कीजिए। समय मुश्किल है, इसलिए सरकार की चिंता समझ में आती है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। जून 2025 में शुरू हुए ईरान–इजरायल संघर्ष का असर स्वाभाविक तौर पर भारत ने भी महसूस किया, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्यकृ जहां से भारत में आयात होने वाले कच्चे तेल के जहाज गुजरते हैंकृ वह ईरानी दबाव के कारण अनिश्चितता के घेरे में आ गया। ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ीं, भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ा, विदेशी निवेश वापस हुआ, और आयात बिल और भी भारी हो गया। ऐसे समय में सरकार नागरिकों से संयम की अपील करना बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस अपील को समझने के लिए 1967 याद करना जरूरी है, क्योंकि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देश से लगभग ऐसी ही अपील की थी। फर्क यह है कि तब का भारत और आज के भारत की आर्थिक वास्तविकताएं बिल्कुल अलग हैं। 1967 में भारत की जीडीपी मुश्किल से 50 अरब डॉलर थी। विदेशी मुद्रा भंडार इतने सीमित थे कि अक्सर कुछ हफ्तों के आयात की भी चिंता खड़ी हो जाती थी। लगातार सूखा पड़ना, 1965 के युद्ध के बाद अमेरिकी खाद्य सहायता रुकना और विश्व बैंक तथा आईएमएफ का दबावकृ इन सबने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां 1966 में रुपये का भारी अवमूल्यन लगभग मजबूरी बन गया। रुपया 4.76 से गिरकर 7.50 प्रति डॉलर पर पहुंच गया और अर्थव्यवस्था उस वर्ष सिकुड़ गई। वह केवल आर्थिक दबाव नहीं थाय बल्कि भारत सचमुच अस्तित्व के संकट से गुजर रहा था।आज का भारत उस दौर से बिल्कुल अलग है। अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, विदेशी मुद्रा भंडार सैकड़ों अरब डॉलर के हैं और दुनिया भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखती है। इसलिए आज की सरकार के लिए स्थिति 1967 जैसी मजबूरी की नहीं, बल्कि देश को बाहरी झटके को संभालने की स्थिति है। लेकिन यहीं एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। अगर भारत इतना सक्षम हो चुका है, तो फिर भी पश्चिम एशिया में हो रहा कोई युद्ध भारतीय रसोईयों तक बेचौनी क्यों पहुंचा देता है? जवाब सीधा है कि तेल और सोने के मामले में हम भी आयात पर निर्भर हैं।सोने का मामला तो और भी दिलचस्प है। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर एक व्यापक चर्चा छेड़ दी थी कि भारतीय घरों, मंदिरों और संस्थानों में लगभग 20,000 टन सोना पड़ा है। सरकार ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम इसी सोच के साथ शुरू की थी कि अगर इस निष्क्रिय सोने का एक हिस्सा भी वित्तीय व्यवस्था में आ जाए तो आयात का दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। तार्किक रूप से यह विचार गलत नहीं था, लेकिन इस पर आधारित योजना भारतीय समाज के सोने में भरोसे की एक गहरी सच्चाई से टकरा गई। भारत में सोना केवल निवेश नहीं है। वह कई पीढ़ियों की आर्थिक विरासत है, और आर्थिक समृद्धि की प्रतीक है। वह उस समाज की सुरक्षा है जिसने बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा करने से पहले सोने पर भरोसा करना सीखा। कई घरों में वह स्त्री की निजी आर्थिक ताकत है, और संकट के समय का सहारा भी है। इसलिए सोना न खरीदना केवल एक आर्थिक सलाह नहीं रह जातीय बल्कि वह लोगों की सबसे पुरानी आर्थिक मानसिकता को शंकित बनाती है। ऐसी आदतें सरकारी अपीलों से नहीं बदलतीं। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें अपने पुराने भरोसे से अधिक विश्वसनीय विकल्प दिखाई दें।हालांकि यह भी साफ रहना चाहिए कि सोने पर संयम से हासिल क्या होता है। अगर सोने का आयात घटता है तो विदेशी मुद्रा पर दबाव कुछ कम पड़ता है, चालू खाता घाटा नियंत्रित होता है और रुपये को थोड़ी राहत मिलती है। यह सब वास्तविक आर्थिक लाभ हैं। लेकिन इससे रोजगार पैदा नहीं होता, किसी की आय नहीं बढ़ती और न ही गरीबी सीधे कम होती है। इसलिए सोने पर संयम को उसी रूप में समझना चाहिए जिस रूप में वह हैकृ एक व्यापक आर्थिक उपाय, न कि सामाजिक समाधान। और यहीं पर बात आती है अपील करने के तरीके की। 1967 में इंदिरा गांधी ने देश से त्याग की अपील की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने सोने के गहने नेशनल रिलीफ फंड में दान कर दिए थे। उस कदम में एक नैतिक शक्ति थी क्योंकि उसमें यह संदेश छिपा था कि जो उम्मीद देश से की जा रही है, सत्ता स्वयं उससे बाहर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राएं टालने की बात कही, लेकिन उसी दौरान उन्होंने अपनी विदेश यात्राएं जारी रखीं और यह नहीं कहा जा सकता कि वे यात्राएं अनावश्यक थींय कूटनीति, व्यापार वार्ताएं और रणनीतिक रिश्ते किसी भी बड़े देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल निर्णय नहीं, उनके प्रतीक भी मायने रखते हैं। जब नागरिकों से संयम की उम्मीद की जाए, तब सरकार से भी यह अपेक्षा स्वाभाविक ही है कि वह बताए कि वे यात्राएं क्यों अनिवार्य थीं, उसका क्या उद्देश्य था, क्या हासिल हुआ और यह बोझ वास्तव में कितना साझा है, सरकार का इसमें कितना योगदान है? यह कोई अनुचित सवाल नहीं है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जन–सामान्य की जिम्मेदारी है। नागरिकों से केवल त्याग मांगना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें विश्वास में भी लिया जाना होता है। शायद यही वह जगह है जहां 1967 और 2026 की अपीलों में बड़ा फर्क दिखाई देता है। 1967 में भारत के पास विकल्प कम थे, इसलिए अपील में मजबूरी साफ दिखाई देती थी। 2026 का भारत कहीं अधिक सक्षम है, इसलिए आज नागरिक अपील तो सुनते हैं, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि सत्ता स्वयं उस पर किस रूप में अमल करती दिखाई देती है। लोकतंत्र में आखिरकार यही बात जनता से किसी भी अपेक्षा की नैतिक विश्वसनीयता तय करती है।

सरकारी स्कूलों की चुनौतियां और बदलता शिक्षा परिदृश्य

अरुण

डनायक शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है। अतरू नीतिगत बदलाव के नाम पर अव्यवहार्य योजनाओं को पुनर्जीवित करने और पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ करने के बजाय, मौजूदा स्कूल अधोसंरचना, शिक्षक क्षमता और शिक्षण गुणवत्ता में निरंतर निवेश करना अधिक आवश्यक है।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की आधारशिला है। शिक्षा पर जीडीपी का 6प्रतिशत व्यय करने की दशकों पुरानी सिफारिश के बावजूद भारत अभी भी लगभग 4.6प्रतिशत पर अटका हुआ है। यह निवेश अंतर सीखने की गुणवत्ता को सीमित करने के अलावा भारत की प्रगति की गहराई, समावेशिता और दीर्घकालिक स्थिरता पर भी संरचनात्मक बाधाएं खड़ी करता है।नीति आयोग की मई 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्कूली शिक्षा संरचनात्मक असंतुलन, अवसंरचना की कमी, शिक्षक संकट और शासन कमजोरियों से जूझ रही है। देश में 7.3 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह संख्या घटकर मात्र 1.42 लाख रह जाती है। प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक निरंतर शिक्षा देने वाले स्कूलों की कमी के कारण छात्रों को बार–बार स्कूल बदलना पड़ता है, जिससे ग्रामीण, गरीब और बालिका विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता प्रभावित होती है। कई विद्यालय न्यूनतम नामांकन के कारण आर्थिक व प्रशासनिक रूप से अप्रभावी हैं। कुछ विद्यालयों में नामांकन न होने के बावजूद वे प्रशासनिक संरचना में बने हुए हैं, जिससे संसाधनों की दक्षता पर प्रश्न उठते हैं। एक गंभीर समस्या एकल–शिक्षक विद्यालयों की है कृ देश में एक लाख से अधिक स्कूलों में एक ही शिक्षक को शिक्षण के साथ प्रशासनिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है।अवसंरचना के स्तर पर पिछले वर्षों में सुधार के बावजूद स्थिति अभी भी चिंताजनक है। नीति आयोग के अनुसार लगभग 1.19 लाख विद्यालयों में बिजली उपलब्ध नहीं है। 14,505 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है और लगभग 60,000 विद्यालयों में हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। बालिका शिक्षा के लिए शौचालयों की कमी गंभीर है। करीब 98,592 स्कूलों में कार्यशील बालिका शौचालय नहीं हैं, जिससे किशोरियों की उपस्थिति और निरंतरता प्रभावित होती है।विज्ञान शिक्षा कमजोर हैकृ मात्र 51.7 प्रतिशत सरकारी माध्यमिक स्कूलों में कार्यात्मक प्रयोगशालाएं हैं। पुस्तकालय मुख्यतरू भंडारण तक सीमित हैं। डिजिटल अवसंरचना की असमानता, विशेषकर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में, नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षण आकलन रिपोर्टें दर्शाती हैं कि अनेक विद्यार्थी कक्षा के अनुरूप पढ़ने और गणितीय दक्षता हासिल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए केवल नामांकन नहीं, सीखने की गुणवत्ता सुधारना भी आवश्यक है।बालिकाओं के नामांकन में बढ़ोतरी के बावजूद, घरेलू काम, बाल विवाह, सुरक्षा, परिवहन और सुविधाओं की कमी के चलते माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर अधिक बनी हुई है। प्रवासी बच्चों की स्थिति बदतर है, वे भाषा, दस्तावेजों की कमी और बार–बार स्कूल बदलने से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। शिक्षकों में पर्याप्त जागरूकता व प्रशिक्षण के अभाव के कारण सीखने की अक्षमताएंकृजैसे डिस्लेक्सिया और डिस्कैल्कुलियाकृ अक्सर पहचान से बाहर रह जाती हैं। भारतीय शिक्षा प्रशासन केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों पर विभाजित है। बहु–स्तरीय प्रशासन में भूमिकाओं की अस्पष्टता और ओवरलैप से निर्णय–प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कई राज्यों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। विद्यालय प्रमुखों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, न कि नेतृत्व क्षमता पर। निरीक्षण प्रणाली शिक्षण गुणवत्ता की अपेक्षा कागजी अनुपालन तक सीमित रहती है। शिक्षक गैर–शैक्षणिक कार्यों (सर्वेक्षण, चुनाव ड्यूटी आदि) में व्यस्त रहते हैं, जिससे वास्तविक शिक्षण समय कम हो जाता है।इन चुनौतियों से परेशान अभिभावक निजी स्कूलों की ओर तेजी से जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूलों का नामांकन 2005 के 71प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 49प्रतिशत रह गया है, जबकि निजी स्कूलों की माध्यमिक स्तर पर हिस्सेदारी 44 प्रतिशत पहुंच गई है। अभिभावक बेहतर अंग्रेजी, अनुशासन और बालकों के भविष्य की उम्मीद में निजी स्कूल चुनते हैं, लेकिन निजी विद्यालयों में भी सीखने के परिणाम कमजोर हैं। कई स्कूल निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते तथा निगरानी भी अपर्याप्त है। यह रुझान सरकारी कमियों के साथ–साथ अभिभावकों की बढ़ती आकांक्षाओं और सामाजिक–आर्थिक दबावों का संकेत भी है। सरकार ने इन चुनौतियों को देखते हुए कुछ कदम उठाये हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूलों को आधुनिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी–सक्षम और हरित आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। 27,360 करोड़ रुपये के निवेश से 5 वर्षों में 18 लाख छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है, हालांकि कार्यान्वयन राज्यों में असमान है। नीति आयोग ने 2017 में झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में सतत कार्रवाई–शिक्षा (एसएटीएच–ई) परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सीखने के परिणामों में सुधार लाना था। प्रारंभिक चरण में 15–18प्रतिशत तक सुधार तथा कम नामांकन वाले हजारों विद्यालयों के विलय जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसी प्रकार राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने भी अपने स्कूल रेशनलाइजेशन कार्यक्रम के तहत बिखरे और कम नामांकन वाले विद्यालयों को एकीकृत कर बेहतर संसाधनों वाले बड़े विद्यालयों में परिवर्तित किया, जिससे शिक्षक तैनाती और अवसंरचना में सुधार हुआ। हालांकि, इन पहलों का प्रभाव सीमित और असमान रहा। राज्यों की प्रशासनिक क्षमता की कमजोरी, शिक्षक रिक्तियां, ग्रामीण विरोध, संस्थागत सीमाएं तथा कोविड–19 जैसी बाधाओं ने इनके दीर्घकालिक और व्यापक प्रभाव को बाधित किया। 2016 से शुरू अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य छात्रों को नवाचार आधारित प्रयोगों से जोड़ना था, लेकिन जटिल प्रक्रिया, संसाधन और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी से कई सरकारी विद्यालय इसका लाभ नहीं उठा सके। बेहतर अवसंरचना के कारण निजी विद्यालयों ने इसका अधिक लाभ उठाया, जबकि सरकारी स्कूलों में यह पहल विज्ञान प्रयोगशालाओं की मूलभूत कमी दूर करने में सीमित रही।

नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ हुए अनुचित व्यवहार के विरोध में सोमवार को राष्ट्रीय छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन के माध्यम से सौंपा। छात्र नेताओं ने कहा कि देश के लाखों विद्यार्थियों ने वर्षों की मेहनत और आर्थिक संघर्ष के बाद नीट परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों पर जांच के नाम पर विद्यार्थियों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। कलावा, जनेऊ, तिलक, मंगलसूत्र और अन्य वस्तुएं उतरवाए जाने से छात्रों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। छात्र परिषद ने मांग की कि नीट पेपर लीक प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कर दोषियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। छात्रों ने परीक्षा रद्द होने से हुए मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए जल्द निष्पक्ष वातावरण में पुनः परीक्षा आयोजित कराने की भी मांग की।

डीजल-पेट्रोल मूल्यवृद्धि और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन,राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में डीजल–पेट्रोल और कामर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना–प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और कामर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि कर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय लोगों को खर्च कम करने की सलाह दे रही है, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट चुकी है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि भाजपा सरकार देश की आर्थिक स्थिति संभालने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से डीजल–पेट्रोल एवं गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव सत्यवीर सिंह, पंकज सोनकर, देवराज पांडेय, विनय तिवारी, शिव मिश्रा, राकेश सिंह डब्बू समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पेंशनर्स, कर्मचारियो व शिक्षको ने स्व. बी. एन. सिंह को संघर्ष संकल्प दिवस के रूप में दी श्रध्दांजलि

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सीबी सिंह की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कार्यालय पर कर्मचारी, पेंशनर्स एवं शिक्षक हितो के लिए आजीवन संघर्षरत रहे मसीहा स्व. बी. एन. सिंह को श्रध्दा सुमन अर्पित कर ,सत्ताइसवी पुण्य तिथि को संघर्ष संकल्प दिवस के रुप मे मनायी गयी। श्रध्दांजलि सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सीबी सिंह ने स्व. बी. एन. सिंह के संघर्ष को याद करते हुए केन्द्र सरकार के समान राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स को महगाई एवं बेतन की समानता दिलाने के लिए किए गए आन्दोलन के साथ ही वर्ष 1994–95 मे पद के दो प्रोन्नत बेतन मान को सरकार से मनवाने के लिए किए गए 51दिन के हड़ताल का स्मरण करते हुए ,वर्तमान केंद्र सरकार के गठित वेतन आयोग के संकल्प पत्र मे पेंशनर्स के टर्म्स रिफरेन्स को सम्मिलित किए जाने तक संघर्ष संकल्प दिवस के रूप मे लेते हुए संघर्ष का संकल्प व्यक्त कर श्रध्दासुमन अर्पित किए। श्रध्दांजलि सभा को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष डाक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने स्व. बी. एन. सिंह के वर्ष 1966 से अपने जीवन के अंतिम दिन 18मई1999 तक कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स के हितो के लिए अनवरत संघर्ष कर जो हक दिलवाया था,उसे सरकार धीरे धीरे बन्द कर रही है। स्व. बी. एन. सिंह केन्द्र के समान राज्य सरकार के कर्मचारियो को भत्तो की समानता के लिए संघर्ष शील रहे,जो काल के क्रुर चक्र ने असमय छीन कर बंचित कर दिया । संरक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा केन्द्र सरकार बैकडोर से सेवानिवृत्त तिथि के आधार पर पेंशनर्स मे जो बीभेद करने का कुचक्र कर रही है उसे हम सब मिलकर सफल नही होने देगे और वित्त बिधेयक 2025वापस करने एवं पेंशनर्स के टर्म्स रिफरेन्स को बेतन आयोग के संकल्प पत्र मे सम्मिलित किए जाने तक संघर्ष का संकल्प ही स्व. बी. एन. सिंह जी को सच्ची श्रध्दांजलि होगी । श्रद्धांजलि सभा को मुख्य रूप से शेषनाथ सिंह, राम अवध यादव, नन्दलाल सरोज, कृष्ण कुमार तिवारी,पलकधारी मौर्य, कंचन सिंह, श्याम बिहारी सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मन्त्री देवेश कुमार यादव,मिठाई लाल, भानुप्रतापश्रीवास्तव, संम्प्रेक्षक राम आश्रय रजक, ओमप्रकाश यादव , राजेन्द्र प्रसाद सिंह, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, ई. प्रमोद कुमार सिंह ,जियाराम यादव, ओकांर नाथ मिश्र, अशोक कुमार मौर्य, राजपति विश्वकर्मा,शम्भूनाथ यादव, गल्लनराम,नरेन्द्र त्रिपाठी वी वी सिह,बिक्रमाजीत यादव, चन्द्र शेखर सिंह, महेन्द्र प्रसाद पाठक, सुक्खुराम, नन्दलाल सरोज, ई. मदन मोहन सोनकर, ओमप्रकाश सिंह, रमाशंकर निषाद,डॉक्टर भारत यादव, मुकुन्दलाल उपाध्याय, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, लाल जी शुक्ला गजराज मौर्य आदि ने श्रध्दासुमन अर्पित करते हुए पेंशनर्स हितो के लिए संघर्ष का संकल्प व्यक्त किया। सभा के अन्त मे दिवंगत पेंशनर्स स्व0 हीरालाल पाण्डेय की आत्मा के शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई । सभा का संचालन जिला मन्त्री कृपाशंकर उपाध्याय ने किया।

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 44 लाख की विदेशी सिगरेट मिली

लखनऊ, (संवाददाता)। चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर भारत लाई गई विदेशी सिगरेट की खेप बरामद की है। बरामद सिगरेट की अनुमानित कीमत 44 लाख 6 हजार रुपये बताई जा रही है। मामले में कस्टम विभाग ने माल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ लखनऊ को 18 और 19 अप्रैल 2026 को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि गाड़ी संख्या 15909 से दीमापुर से लखनऊ तक बुक होकर आए पार्सलों में संदिग्ध सामान मौजूद है। सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल ने पार्सल कार्यालय में पहुंचे कुल आठ नगों की निगरानी शुरू कर दी और मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक को निर्देश दिए कि डिलीवरी आरपीएफ की मौजूदगी में ही कराई जाए। हालांकि काफी समय तक कोई भी व्यक्ति पार्सल लेने नहीं पहुंचा। इस बीच आरपीएफ को पुख्ता जानकारी मिली कि पार्सलों में विदेशी सिगरेट भरी हुई है। इसके बाद मामले की सूचना कस्टम विभाग और राज्य कर विभाग को दी गई। गुरुवार को आरपीएफ लखनऊ, अपराध आसूचना शाखा, कस्टम विभाग और राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने पार्सलों की जांच की।

स्वस्ति वाचन एवं गायत्री मंत्र के साथ संपन्न हुआ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कर्नाटक का वार्षिक समारोह

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

बेंगलुरु। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कर्नाटक का वार्षिक समारोह गायत्री चेतना केंद्र, बेंगलुरु के सभागार में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पत्रकार हितों, ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियों तथा संगठन द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के संयोजक अतुल कपूर ने बताया कि प्रेस क्लब परिसर में आंधी–तूफान के दौरान पेड़ गिर जाने के कारण कार्यक्रम स्थल को अंतिम समय में परिवर्तित करना पड़ा, इसके बावजूद बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि शेखर चतुर्वेदी द्वारा स्वस्तिवाचन एवं गायत्री मंत्र के साथ केक काटकर किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं, प्रतिभाओं तथा सामाजिक सरोकारों को सामने लाने में ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पत्रकार केवल समाचार संकलन का कार्य नहीं करता, बल्कि समाज को दिशा देने का दायित्व भी निभाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने पत्रकारों से सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देने, समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने तथा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित करने का आह्वान किया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष अतुल कपूर ने संगठन की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण एवं छोटे कस्बों में कार्य करने वाले पत्रकार अनेक कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित संसाधान एवं सुरक्षा नहीं मिल पाती। इसी उद्देश्य से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पत्रकारों के हितों की रक्षा, संगठनात्मक मजबूती तथा पत्रकारों को सामाजिक पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा विभिन्न राज्यों में पत्रकारों को जोड़ने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, पत्रकार उत्पीड़न के मामलों में प्रशासनिक स्तर पर सहयोग करने तथा जरूरतमंद पत्रकारों की सहायता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रकारों को डिजिटल पत्रकारिता, मीडिया नैतिकता एवं सामाजिक सरोकारों से जोड़ने हेतु समय–समय पर कार्यशालाएं एवं विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। अतुल कपूर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में सात राज्यों में संगठन की प्रदेश कार्यकारिणियों का गठन किया जा चुका है तथा पांच राज्यों में संगठन विस्तार की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि जून माह के अंतिम सप्ताह में तेलंगाना राज्य में भी प्रदेश संयोजक एफ. एम. सलीम के नेतृत्व में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अजय कुमार वाली ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के बीच पत्रकारों के सामने विश्वसनीयता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को निष्पक्षता, सत्यता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि अजय गुप्ता ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के विस्तार एवं पत्रकार हितों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए संगठन को पूरे कर्नाटक में मजबूत बनाने हेतु हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। आचार्य कमलेश खरे ने मंगल तिलक लगाकर एवं गायत्री मंत्र अंकित अंगवस्त्र भेंट कर अतुल कपूर, अजय कुमार वाली एवं अजय गुप्ता का स्वागत एवं सम्मान किया। इस अवसर पर आलोक दीप, मनमोहन सिंह राठौर व प्रपन्न मंडल सहित अनेक पत्रकारों एवं गणमान्य लोगों ने पत्रकार एकता, सामाजिक सरोकार एवं संगठन की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए।

लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में जौनपुर के वकीलों का प्रदर्शन कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ता, डीएम को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में लखनऊ में अधिवक्ताओं के चौंबरों पर बुलडोजर कार्रवाई और वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव एवं मंत्री रण बहादुर यादव के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन को ज्ञापन सौंपा।

अधिवक्ताओं ने कहा कि अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज कराना अत्यंत निंदनीय है तथा यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज न्यायपालिका का अभिन्न अंग है, जो संविधान और कानून की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

वक्ताओं ने कहा कि वकीलों के चौंबरों को ध्वस्त करना उनके अधिकारों का हनन है और इससे न्यायिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अधिवक्ताओं ने मांग की कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के लिए स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ध्वस्त चौंबरों को पुनः स्थापित कराया जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट बार अध्यक्ष घनश्याम सिंह, मंत्री मनोज मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी।

लखनऊ पुलिस और 'प्रयास' की पहल स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा का पाठ

लखनऊ, (आरएनएस)डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए लखनऊ पुलिस साइबर क्राइम सेल ने स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ पुलिस साइबर क्राइम सेल एवं गैर सरकारी संस्था 'प्रयास' के संयुक्त तत्वावधान में मॉडर्न एकेडमी स्कूल में विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 07 एवं 08 के छात्र–छात्राओं को इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई ।कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को बढ़ते साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र–छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की ।मॉडर्न एकेडमी स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें समझाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत फोटो, मोबाइल नंबर, घर का पता, बैंक संबंधी जानकारी और अन्य निजी सूचनाएं साझा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। बच्चों को सलाह दी गई कि वे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट अथवा लॉक रखें और केवल परिचित लोगों को ही अपनी मित्र सूची में शामिल करें।कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों की भी जानकारी दी गई। साइबर क्राइम सेल के मुख्य आरक्षी गौरव शुक्ला ने बच्चों को बताया कि अनजान नंबरों से आने वाले लिंक, संदिग्ध मैसेज, ओटीपी या फर्जी फाइल्स को बिना जांच–परख के खोलना मोबाइल फोन और निजी डाटा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने विशेष रूप से फर्जी एपीके (।च्ज्ञ) फाइल्स और मालवेयर के खतरों के प्रति सावधान करते हुए कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन केवल विश्वसनीय और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करनी चाहिए।बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से बातचीत करना, पैसे का लेन–देन करना या निजी जानकारी साझा करना साइबर ठगी का कारण बन सकता है।

रोटरी क्लब जौनपुर द्वारा क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम संपन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। रोटरी क्लब जौनपुर द्वारा टीबी मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई ।प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ विशाल सिंह यादव की अध्यक्षता में टीबी मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष

विवेक कुमार सेठी संयोजक मिथिलेश कृष्ण कुमार मिश्रा श्री श्याम वर्मा श्याम जयसवाल उपस्थित रहे ।पोषण पोटली कार्यक्रम का संचालन डॉ सुशील अग्रहरी ने किया ।इस अवसर पर सुरेंद्र निषाद राजीव श्रीवास्तव नितिन मौर्य देवेंद्र प्रजापति नंदकिशोर सभी सदस्य कर्मचारी एवं अन्य टीबी के मरीज उपस्थित रहे।

बस पलटने से परिचालक की मौत,पांच घायल सभी सुरक्षित पुलिस ने शव को बस को लिया कब्जे में

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित सुजानगंज थाना अंतर्गत सोमवार दोपहर प्रयागराज से बदलापुर जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटने से परिचालक की मौत हो गई। जबकि बस में सवार 5 यात्री घायल हो गए। अमन बस सर्विस की प्राइवेट बस प्रयागराज से सवारी भरकर बदलापुर की ओर आ रही थी। दोपहर में बस रामनगर पहुंचने पर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पूर्वी ओर खाई में पलट गई। बस खाई में पलटने का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका, कुछ लोग चालक को झपकी तो कुछ लोग स्टेरिंग फेल होने की बात कर रहे हैं।फिलहाल यह जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि बस किन कारणों से खाई में पलटी। बस पलटने से बस गंभीर रूप से घायल बस परिचालक को एंबुलेंस से

महराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां कंडक्टर की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक परिचालक का नाम और पता नहीं चल सका है। वही महोबा जनपद के भगड़ी गांव निवासी भैया लाल(50) का परिवार बदलापुर किसी रिश्तेदार के यहां जा रहा था। बस दुर्घटना में भैया लाल और उनके परिवार के नंदकिशोर (35)अरविंद(23)उर्मिला(50)भगती (35)घायल हो गई जो निजी चिकित्सकों द्वारा इलाज करा कर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शेष यात्रियों को दूसरे वाहनों से में बिठाकर बदलापुर की ओर रवाना कर दिया।इस मामले में थानाध्यक्ष अमित ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर बस को बाहर निकालते हुए लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है जबकि परिचालक की जिला अस्पताल में मौत हो गई है।शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है बस को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षकों से मिला अथाह प्रेम मुझे संघर्ष करने के लिए करता है प्रेरित –ध्रुव कुमार त्रिपाठी

अयोध्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अयोध्या के तत्वावधान में सोमवार को राजकीय अतिथि गृह (सर्किट हाउस) में शिक्षक – विधायक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया ।गोरखपुर – फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जिले के प्रधानाचार्यो और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद बनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया था ।शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जिले की समस्याओं को शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों से सुनकर तत्काल जिले के अधिकारियों को निस्तारण करने का आदेश दिया ।इस अवसर पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते

हुए शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को वह सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करते रहे ।इससे पहले शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने राजकीय पुस्तकालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मेधावी छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया ।मेधावी छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के छात्र छात्रा कल के भविष्य हैं। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी, राजकीय पुस्तकालय प्रभारीः एडीआईओएस अवनीश कुमार पांडे वित्त एवं लेखाधिकारी अनुपम कुमार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी व प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

बैंक में नकली नोट जमा करने पहुँचा युवक गिरफ्तार

लखनऊ(आरएनएस),चिनहट थाना पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा करने के मामले में नामजद एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक ऑफ बड़ौदा की चिनहट शाखा में 33 हजार रुपये जमा करने पहुंचा था, जहां जांच के दौरान 500 रुपये के 14 नकली नोट मिलने पर बैंक प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और बरामद नकदी के संबंध में जांच की जा रही है ।पुलिस के अनुसार, थाना चिनहट में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 258ध्26 धारा 179 भारतीय न्याय संहिता के । को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है।

भीषण गर्मी मे भी राम मंदिर मे उमड़ रही श्रद्धालुओ की भारी संख्या में भीड़

अयोध्या। तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद भी राम जन्मभूमि मंदिर में राम भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है।और यह भी पिछले दिनों की अपेक्षा लगातार बढ़ ही रही है।रविवार को लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का दर्शन पूजन किया।भीड़ का आलम यह रहा कि एसपी सुरक्षा खुद कमान संभाल रहे है। भीड़ को देखते हुए गत दिनों की अपेक्षा इधर सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है।देखा जाए तो इस समय जहां शनिवार और रविवार को दो दिन वीकेंड के चलते भीड़ बढ़ना स्वभाविक था वही अब बच्चों की छुट्टियों के चलते भी अब और भी भारी संख्या में रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं के अंदाजा लगाया जा रहा है।क्योंकि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी मथुरा,वाराणसी जाने वाले श्रद्धालु अयोध्या भी आएंगे और रामनगरी में भी भारी संख्या में होगी इसको देखते हुए अभी से ही पुलिस प्रशासन भी रणनीति बनाने में जुट गई है।इस प्रचंड गर्मी में रविवार को छोड़े तो सोमवार को भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भी देखी गई जो दोपहर के दौरान भी बनी रही।सुबह शाम राम मंदिर के अलावा हनुमानगढी, कैकई भवन, राम की पैड़ी,जानकी महल ट्रस्ट, नागेश्वर नाथ सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ दिखी। इस संबंध में सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने खुद माना कि इधर पिछले तीन–चार दिनों से श्रद्धालुओं के भीड़ में बढ़ोतरी हुई है और आगे उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चों की छुट्टी होने के चलते रामनगरी में और भी भीड़ होगी।जिसके चलते हनुमानगढी, कनक भवन, राम की पैड़ी, सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है और वहां की सारी गतिविधियों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखी जा रही है।बताया कि इधर गर्मी के चलते श्रद्धालुओं के डूबने की संख्या में इजाफा हुआ है।इसके लिए भी सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर पर्याप्त संख्या में जल पुलिस एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। क्योंकि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ इन घाटों पर भी दिखाई देगी।

रामजन्मभूमि परिसर में 23 जून को शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण, दोनों डिप्टी सीएम को न्योता

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।रामजन्मभूमि परिसर स्थित शेषावतार मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण अगले माह 23 जून को किया जाएगा।इसके लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रित किया है।आयोजन में देशभर से संत–धर्माचार्य, धार्मिक संगठन, जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े करीब एक हजार लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा।ट्रस्ट ने अभी 29 मई को प्रस्तावित मां दुर्गा मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। इसी कारण अतिथियों की सूची और आयोजन की विस्तृत रूपरेखा पर अभी अंतिम चर्चा नहीं हो सकी है।ट्रस्ट की ओर से रामजन्मभूमि परिसर के सभी पूरक मंदिरों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को विशेष स्वरूप दिया जा रहा है। परकोटे के पांच पूरक मंदिरों पर पहले ही ध्वजारोहण हो चुका है।छठे पूरक मंदिर यानी मां दुर्गा मंदिर पर ध्वजारोहण 29 मई को प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम साध्वी ऋतंभरा के हाथों संपन्न होगा।इस अवसर पर दुर्गा वाहिनी सहित विभिन्न महिला संगठनों की करीब दो हजार महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया है।ट्रस्ट ने अब शेषावतार लक्ष्मण जी मंदिर पर ध्वजारोहण की तारीख भी तय कर दी है।दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में करीब एक हजार अतिथियों के बीच इस मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। यह रामजन्मभूमि परिसर का अंतिम पूरक मंदिर होगा। इसके साथ ही पूरक मंदिरों के ध्वजारोहण कार्यक्रमों का क्रम भी समाप्त हो जाएगा।राम मंदिर के पीछे दक्षिण–पश्चिम दिशा में बने शेषावतार मंदिर में भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा की स्थापना गत वर्ष 5 जून को अन्य पूरक मंदिरों के साथ की गई थी। ट्रस्ट ने इस मंदिर में 13 अप्रैल से श्रद्धालुओं के दर्शन भी शुरू करा दिए हैं।

अयोध्या में नयाघाट चौकी क्षेत्र में अतिक्रमण का बोलबाला, श्रद्धालु परेशान

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।थाना कोतवाली अयोध्या के नयाघाट चौकी क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लता चौक से लेकर सरयू पुराने पुल तक सड़क किनारे ठेले और दुकानों का कब्जा होने से आम लोगों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह अतिक्रमण खुलेआम पुलिस चौकी के संरक्षण में हो रहा है और सुविधा शुल्क लेकर ठेले लगवाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।नयाघाट क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु सरयू स्नान और रामनगरी दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सड़क पर फैले अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। सबसे अधिक दिक्कत लता मंगेशकर चौक और धर्म पथ पर देखने को मिल रही है,जहां श्रद्धालुओं के लिए बना सेल्फी प्वाइंट अब अव्यवस्था का केंद्र बनते जा रहे हैं।इसके अलावा गोल्फ कार्ट चालकों की मनमानी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। सड़क पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात के कारण पैदल चलने वालों को भी जोखिम उठाना पड़ रहा है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने, गोल्फ कार्ट संचालन को व्यवस्थित करने की मांग की है।

दरोगा की फिर आई मनमानी सामने,कुछ दिन पहले एसएसपी ने किया था एक महिला दरोगा को लाइन हाजिर

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जिले के बीकापुर कोतवाली में तैनात एसआई रजत सिंह द्वारा गलत ढंग से चेकिंग लगाकर की जा रही है।धन उगाही मामला कल शाम लगभग 7 बजे का है। जिसमें एक अधिवक्ता बीकापुर किसी काम से आया था। भारती स्कूल के सामने स्टेशन मोड़ पर खड़े प रजत सिंह व कुछ अन्य कांस्टेबलों को लेकर खड़े थे।तभी जब अधिवक्ता अपनी मोटरसाइकिल लेकर सामान खरीदने के लिए किराना की दुकान पर मुड़े।तुरंत वहां खड़े दरोगा रजत सिंह द्वारा अधिवक्ता को रोक कर बदतमीजी से बात की गई और अधिवक्ता की गाड़ी का चालान भी कर दिया। अधिवक्ता द्वारा बताया गया सिर्फ मेरी ही गाड़ी का चालान किया गया है और अन्य गाड़ियां आ जा रही थी उनका चालान नहीं हुआ है।एसआई रजत सिंह द्वारा मनमानी ढंग से विधि विरुद्ध अधिवक्ता की गाड़ी का चालान किया गया है।जिसकी शिकायत अधिवक्ता ने एसएसपी से की और दरोगा रजत सिंह से खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीकापुर के अधिकतर लोगों का कहना है रोज स्टेशन मोड़ के पास दर्जनों वर्दीधारी खड़े होकर पूरे क्षेत्र की चेकिंग यही करते है अक्सर यही से उनका कर्तव्य पूरा होता है।

पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं मिलने से भड़के किसान, सड़क पर ट्रैक्टर खड़े कर लगाया जाम– आवागमन ठप

गोरखपुर, (संवाददाता)। क्षेत्र में गहराते डीजल संकट ने अब किसानों की चिंता को आंदोलन में बदल दिया है। शनिवार सुबह परतावल क्षेत्र के पिपरपाती स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल लेने पहुंचे किसानों का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब घंटों इंतजार के बाद उन्हें बताया गया कि पंप पर डीजल उपलब्ध नहीं है। देखते ही देखते नाराज किसानों ने ट्रैक्टर और बाइक सड़क पर खड़ी कर गोरखपुर–महराजगंज मुख्य मार्ग जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 15 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि भोर से ही आसपास के गांवों के किसान ट्रैक्टर, ड्रम और गैलन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे। किसान खेतों की जुताई, धान की नर्सरी और सिंचाई के लिए डीजल लेने आए थे, लेकिन लगातार इंतजार के बाद भी डीजल नहीं मिला। इससे नाराज किसानों ने प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि आम किसानों को डीजल नहीं दिया जा रहा, जबकि चुनिंदा लोगों को आधी रात को तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि इस समय धान की नर्सरी डालने और खेत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है। यदि समय पर डीजल नहीं मिला तो खेती पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर बंद पड़े हैं, सिंचाई रुक गई है और खेतों की तैयारी नहीं हो पा रही। कई किसानों ने चिंता जताई कि यदि यही हाल रहा तो इस बार खेत परती रह जाएंगे और उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा।

20 मई को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के सामने की सभी दवा दुकानों को बंद रखने का ऐलान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर स्थानीय दवा व्यवसायियों में गहरा आक्रोश है।आरडीएमसी मेडिकल एसोसिएशन दर्शन नगर ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए 20 मई को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के सामने की सभी दवा दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है।संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री न केवल छोटे दवा व्यवसायियों की आजीविका पर हमला है, बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन से भी खिलवाड़ है। आरडीएमसी मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र तिवारी उर्फ बाबा ने कहा कि कुछ कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स आकर्षक छूट और सुविधा का लालच देकर लोगों को ऑनलाइन दवाएं खरीदने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह एक सुनियोजित कुचक्र है, जिसका मकसद देशभर के छोटे–मोटे दवा व्यवसायियों को बर्बाद करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि हम देश के हित में इस साजिश को कभी सफल नहीं होने देंगे।ज्ञानेंद्र तिवारी बाबा ने बताया कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाएं बेचना खतरनाक है। कई बार गलत दवा या एक्सपायरी प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंच जाता है,जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पारंपरिक दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट मौजूद रहते हैं जो दवा के बारे में सही सलाह दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह सुविधा नहीं मिलती। इससे मरीजों का जीवन जोखिम में पड़ रहा है।इस हड़ताल को मजबूती देने के लिए आरडीएमसी मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र तिवारी बाबा, रोहित बिजलानी, सूचना मंत्री अभिषेक तिवारी, कोषाध्यक्ष संजीत सोनी ,सुनील मिश्रा, विशाल यादव, हर्ष श्रीवास्तव, रवि गुप्ता, अनुराग पाठक, अभिषेक वर्मा समेत संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।बैठक में सर्वसम्मति से 20 मई को पूर्ण बंदी का फैसला लिया गया। सभी दवा व्यवसायियों से अपील की गई कि वे इस हड़ताल में पूर्ण रूप से भाग लें और दुकानें बंद रखें। संगठन का कहना है कि यदि सरकार और संबंधित विभागों ने ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक नहीं लगाई तो भविष्य में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे।दवा व्यवसायी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय से भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि दवाएं कोई सामान्य वस्तु नहीं हैं, इन्हें बिना निगरानी के बेचना जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

बकरीद पर्व को लेकर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। डीएम शशांक त्रिपाठी एवं एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में आगामी बकरीद पर्व के दृष्टिगत सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।बैठक में जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, विभिन्न समुदायों के सम्मानित नागरिकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की।बैठक में डीएम ने कहा कि बकरीद का पर्व आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांति का प्रतीक है।उन्होंने सभी से प्रशासन का सहयोग करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि साफ–सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए। एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा सोशल मीडिया पर भी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल प्रशासन एवं पुलिस को जानकारी देने की अपील की।बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं एवं गणमान्य नागरिकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने की बात कही।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी,नगर मजिस्ट्रेट,उप जिलाधिकारीगण,सीओ,नगर निकायों के अधिकारी तथा विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शिक्षा के नाम पर लूट खसोट करने वाले विद्यालयों पर समिति कसेगी शिकंजा

अयोध्या।स्ववित्त पोषित विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर लूट खसोट मची हुई है।जिसकी शिकायत डीआईओएस कार्यालय मे लगातार आ रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए डीएम शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता मे एक बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे सीडीओ केके सिंह व बीएसए लाल चंद्र सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।इन पर शिकंजा कसने के लिए समिति का गठन किया गया।समिति में डीएम शशांक त्रिपाठी अध्यक्ष तथा डीआईओएस डाक्टर पवन कुमार तिवारी सदस्य सचिव है।वही जैन बंसल एंड कंपनी अयोध्या के चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्त एंव लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अभिभावक प्रतिनिधि अभिभावक शिक्षक संघ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और प्रधानाचार्य राष्ट्रीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज पिठला को सदस्य बनाया गया है।डीआईओएस डॉ पवन कुमार तिवारी ने बताया कि शिक्षा के नाम पर लूटखसोट करने वाले विद्यालय प्रबंधन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि विद्यालयों से विगत वर्ष के शुल्क के विवरण जिस खाते में प्राप्त किया गया है कक्षा वार उसका विवरण दें।पिछले 5 वर्षों में कितनी बार शुल्क की बढ़ोतरी की गई है और किस मध्य में कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है।कार्यालय मे प्रस्तुत करे।इन कालेजों मे पुस्तक कितने वर्ष में बदली गई है साथ ही साथ ड्रेस में अगर बदलाव किया गया उसका भी विवरण दे। वही साथ ही साथ वेबसाइट का विवरण दें।

सड़क पर दो पक्षों में पथराव, आयुष मंत्री का रुका काफिला- पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा

गोरखपुर, (संवाददाता)। गुलरिहा इलाके में निर्माणाधीन मकान से पानी के छींटे पड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर ईंट–पत्थर चलने लगे। इसी दौरान उसी मार्ग से गुजर रहे आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र श्दयालुश के काफिले को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी पथराव की चपेट में आने से बाल–बाल बच गए। मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भटहट निवासी बरकतुल्लाह, अब्दुल जब्बार, सद्दाब उर्फ छोटू, सगीर अहमद तथा चिलबिलवा निवासी असजद, फरद्दीन, साहिल और मेहंदी हसन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, बड़हरिया निवासी बरकतुल्लाह का मकान निर्माणाधीन है। शुक्रवार को गांव के ही जब्बार अली वहां से गुजर रहे थे, तभी उन पर पानी के छींटे पड़ गए, जिससे कहासुनी शुरू हो गई। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। आरोप है कि इसके बाद बरकतुल्लाह ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में फिर विवाद बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया। इसी दौरान आयुष मंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा था। स्थिति को देखते हुए एस्कॉर्ट में तैनात चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्रा ने वाहन रुकवाकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर–बितर किया। इसके बाद मंत्री का काफिला आगे रवाना किया गया। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चेकिंग के दौरान आरपीएफ प्रभारी हरीश शाही ने स्टेशन परिसर को खंगाला

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।पिछले दिनों अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर नाबालिक बालिका के साथ छेड़खानी के मामले को गंभीरता से लेते हुए रविवार को प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन हरीश शाही ने अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ कैंट स्टेशन परिसर मे सघन चेकिंग अभियान चलाया।उन्होंने यह अभियान स्टेशन परिसर के अंदर सभी प्लेटफॉर्मों, आरक्षण टिकट काउंटर, सर्कुलेटिंग एरिया, बाहर बने वाहन स्टैंड, पीआरएस, आदि जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया।इस मौके पर उन्होंने इधर से गुजरने वाले ट्रेनों कई कोच के अंदर व प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, आरक्षण केन्द्र, सहित अन्य जगहों पर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया और कई यात्रियों के सामानों को भी खोल कर देखा।इस मौके पर उन्होंने रेल यात्रियों से अपील किया कि आप सभी किसी भी संगीत अवस्था में पड़े वस्तुओं को ना उठाएं अगर किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखे तो इसकी सूचना जीआरपी तथा आरपीएफ सुरक्षा कर्मियों को दें।चेकिंग अभियान के दौरान स्टेशन परिसर के अंदर तथा स्टेशन परिसर के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में जो भी व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए उन्हें थाने पर लाकर उनसे पूछताछ किया और संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद ही उन्हें जाने दिया। चेकिंग अभियान के दौरान उन्होंने अतिक्रमण किए हुए कई दुकानदारों की रिक्शा चालकों तथा अन्य वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही किया और सत्य हिदायत दिया कि अगर कोई वाहन चालक या दुकानदार स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया में अतिक्रमण करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने रेल यात्रियों से कहा कि अगर आप सभी को स्टेशन परिसर के साथ – साथ ट्रेन में कोई संदिग्ध अवस्था में वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना जीआरपी व आरपीएफ को दें। जिस समय रहते किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके।

दो दिन बाद भी 25 फीसदी क्षेत्र में ही बहाल हो पाई बिजली

उन्नाव, (संवाददाता)। सफीपुर–मियागंज क्षेत्र में बुधवार को आई आंधी से 200 से अधिक बिजली के पोल टूट गए थे। विभाग ने रात–दिन काम कराने के बावजूद अभी तक 25 फीसदी क्षेत्र में आपूर्ति बहाल हो सकी है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने में अभी दो दिन का समय और लग सकता है। आंधी से सफीपुर क्षेत्र के मोही खेड़ा, गौरी, निहालपुर, मवई भान, सलींद, देवागांव, खरगौरा, मेथीटिकुर, अमबहरा आदि गांव के 71 पोल गिर गए। ट्रांसफार्मर भी ध्वस्त हो गए थे। उपकेंद्र अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि शुक्रवार रात तक परियर मार्ग व अन्य निकट गांव में आपूर्ति बहाल हो जाएगी। खरगौरा, मेथीटिकुर क्षेत्र में 48 घंटे का और समय लग सकता है। मियागंज उपकेंद्र क्षेत्र में करीब 120 पोल गिरने से बिजली आपूर्ति ध्वस्त हो गई थी। एसडीओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मियागंज कस्बे में बिजली बहाल हो गई है। अन्य स्थानों पर भी खंभे खड़े कर लाइन खींची जा रही है। शुक्रवार शाम तक 50 क्षेत्र की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। टीम रात–दिन काम में जुटी है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल होने में 48 घंटे का समय लग सकता है। बुधवार को आई आंधी के कारण बिछिया और आसपास के करीब 50 गांवों में चरमराई बिजली आपूर्ति अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। कई स्थानों पर विद्युत पोल और लाइनें क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति ठप है। शुक्रवार दोपहर बाद केवल पड़री फीडर की आपूर्ति ही बहाल हो सकी है। पड़री कलां और बदली खेड़ा प्राथमिक विद्यालय के पास टूटे पोल अभी तक नहीं बदले गए हैं। इससे सैकड़ों घरों में बिजली नहीं आ रही है जिससे लोग परेशान हैं। जेई श्रवण कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत कर पड़री फीडर की आपूर्ति बहाल की गई है। कहा कि क्षतिग्रस्त पोल की संख्या और स्थान मुख्यालय को भेज दिए गए हैं।

बकरीद पर्व को लेकर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।डीएम शशांक त्रिपाठी एवं एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में आगामी बकरीद पर्व के दृष्टिगत सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।बैठक में जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, विभिन्न समुदायों के सम्मानित नागरिकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की।बैठक में डीएम ने कहा कि बकरीद का पर्व आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांति का प्रतीक है।उन्होंने सभी से प्रशासन का सहयोग करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि साफ–सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए। एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा सोशल मीडिया पर भी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल प्रशासन एवं पुलिस को जानकारी देने की अपील की।बैठक में उपस्थित धर्मगुरुओं एवं गणमान्य नागरिकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने की बात कही।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी,नगर मजिस्ट्रेट,उप जिलाधिकारीगण,सीओ,नगर निकायों के अधिकारी तथा विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।